1	2	3	4	5
दादर एवं नागर हवेली	—	1	—	—
दमन एवं दीव	—	1	—	—
पांडिचेरी	—	1	—	—
	16	181	143	5

टिप्पणी:—

उ.श.ट्रा. — उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ.श.ट्रा. — अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ.अ.श.ट्रा. — अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

Strike Notice by All India Regional Rural Bank Employees Association

1302. DR. BIPLAB DASGUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all India Regional Rural Bank Employees Association (AIRRBEA) has given a notice for strike on 29th and 30th March, 1996 to Government;

(b) if so, what are their demands;

(c) what steps Government propose to take to fulfil their demands;

(d) whether Governmet have started negotiations with the Association; and

(e) if so, the progress thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) The All India Regional Rural Bank Employees Association (AIRRBEA) has indicated its intention of a strike on 29th and 30th March, 1996.

(b) The demands of the AIRRBEA are (i) immediate release of 6th Bipartite benefits to employees of Regional Rural Banks (RRBs); (ii) total restructuring of RRBs with the formation of National Rural Bank of India (NRBI) or Zonal Rural Bank (ZRB) under single central agency (iii) immediate amendment of promotion rules; (iv) retirement benefits including pension scheme as per industry-wise settlement; (v) withdrawal/no coverage of RRBs under the present pension Ordinance on 17.10.95 and 5.1.96; (vi) immediate release of computer increment; (vii) immediate release of National Industrial Tribunal (NIT) arrears to RRB staff.

(c) to (e) Governemt have taken up comprehensive revamping of RRBs on a 'Stand Alone' basis, through infusion of equity to select RRBs as well as other policy measures.

Action has been initiated to finalise the recruitment and promotion rules in consultation with Department of Personnel & Training and Ministry of Law and other agencies.

The issue of release of National Industrial Tribunal arrears to employees of RRB is sub-judice in the Supreme Court. Government have already presented in the Supreme Court a scheme for payment of these arrears.

The other demands having a bearing on the viability of the RRBs should be seen in the context of the overall revamping process.

NRIs Deposits in Indian Share Market

1303. SHRI MOOLCHAND MEENA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a large proportion of Non-Resident Indians (NRIs) deposits in India are in the share market; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) and (b) Total Foreign Currency deposits by Non-Resident Indians (NRIs) at the end of November, 1995 amounted to US $ 16.584 billion, compared to which the NRI investments in the secondary market represent only a small proportion.

राष्ट्रीय पन बिजली निगम की पन-बिजली परियोजनाएं

1304. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सत्तर के दशक के दौरान पन बिजली उत्पादन क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पन बिजली निगम की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा अब तक कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की गई और उनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या इन सभी परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो गया और उनके निर्माण पर कितनी लागत आयी; और

(घ) यदि नहीं, तो मार्च, 1993 तक कितने प्रतिशत परियोजनाएं अपने निर्धारित समय में पूरी की जा सकीं और समय से पूरा न हो पाने के कारण शेष परियोजनाओं की निर्माण लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) जी, हां। जल विद्युत शक्ति का इसके सभी पहलुओं में एक एकीकृत एवं कुशल विकास हेतु आयोजना, प्रवर्तन तथा स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) की वर्ष 1975 में स्थापना की गई थी।

(ख) एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु 3573 मे०वा० की कुल विद्युत क्षमता के लिए सरकार द्वारा अभी तक 11 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) उक्त 11 परियोजनाओं में से 16353 मे०वा० की कुल विद्युत उत्पादन-क्षमता के लिए एनएचपीसी द्वारा अभी तक 6 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिनमें समय और लागत अधिक लगी है। पांच परियोजनाओं, जिनको अभी पूरा किया जाना है, में भी भिन्न-भिन्न मात्रा में समय व लागत अधिक लगेगी। पूरी की गई 6 परियोनजाओं के निर्माण की लागत में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)। लागत में वृद्धि, समय अधिक लगने तथा विभिन्न अन्य घटकों यथा; मूल्य अभिवृद्धि, विनिमय दर परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन तथा वित्त पोषण के तरीके में परिवर्तन आदि के कारण हुई है।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	परियोजना हाथ में लेने के समय इसे पूरा करने का वास्तविक कार्यक्रम	पूरा करने की तिथि	एनएचपीसी द्वारा परियोजना हाथ में लेने के समय इसकी अनुमानित लागत (मूल्यस्तर)	पूरा करने की लागत (मूल्यस्तर)	लागत में वृद्धि %
1	2.	3	4	5	6	7	8
1.	पैप स्यूल एचई परियोजना (हि०प्र)	198 मे०वा	जून, 81	दिसंबर 1981	108.85 (3/79)	148.34 (10/81)	36.28